



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182]

No. 182]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 2003/कार्तिक 16, 1925

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 2003/KARTIKA 16, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 4 नवम्बर, 2003

सं. टीएएमपी/87/2002-टीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा, मेनलाइन कंटेनर जलयानों पर पैकेज समुद्री प्रभार लगाए जाने के बारे में आदेश सं. टीएएमपी/87/2002-टीपीटी दिनांक 17 मार्च, 2003 द्वारा पहले अनुमोदित सशर्तताओं में से एक सशर्तता में संशोधन करने के लिए तृतीकोरिन पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का, संलग्न आदेशानुसार, अनुमोदन करता है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी/87/2002-टीपीटी

तृतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी)

आवेदक

आदेश

(अक्तूबर, 2003 के 22वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने मेनलाइन कंटेनर जलयानों पर पैकेज समुद्री प्रभार लगाने के लिए तृतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए दिनांक 17 मार्च, 2003 को प्रकरण सं. टीएएमपी/87/2002-टीपीटी में एक आदेश पारित किया था। उक्त आदेश 19 अप्रैल, 2003 को राजपत्र सं. 59 द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

1.2. पैकेज समुद्री प्रभार की अर्हता के संदर्भ में, इस प्राधिकरण ने अपने आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ पत्तन द्वारा यथा प्रस्तावित पैरा 6 (iv) में निम्नलिखित सशर्तता अनुमोदित की थी :-

"(iv). यह योजना इस शर्त पर वैयक्तिक लाइनों अथवा इनके संगठन पर लागू होगी कि यह संगठन कम से कम 5 वर्षों से प्रस्थापित पंजीकृत संस्था होनी चाहिए और यह संगठन यह विनिर्दिष्ट करे कि इसके सदस्य अलग-अलग कितनी बार पत्तन में आएंगे।"

2.1. टीपीटी ने दिनांक 6 अक्तूबर, 2003 के अपने पत्र में कहा है कि वैयक्तिक लाइनों अथवा इनके संगठन के मामले में पैकेज समुद्री योजना में सन्निहित लाभ प्राप्त करने के लिए पाँच वर्षों की प्रस्थापना निर्धारित करने की उक्त शर्त बहुत ही कठोर मानी गई है। इसने उल्लेख किया है कि इस अनुबन्ध को पूर्वव्यापी प्रभाव अर्थात् 1 अप्रैल, 2003 से समाप्त करने और इस खंड को निम्नलिखित रूप में निर्धारित करने पर आम सहमति है :-

"(iv). यह योजना इस शर्त पर वैयक्तिक लाइनों अथवा इनके संगठन पर लागू होगी कि यह संगठन एक पंजीकृत संस्था होनी चाहिए और यह संगठन यह विनिर्दिष्ट करे कि इसके सदस्य अलग-अलग कितनी बार पत्तन में आएंगे।"

2.2. प्रस्तावित संशोधन से उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा। चूंकि प्रस्तावित संशोधन कथित रूप से आम सहमति पर आधारित है, इसलिए इस प्राधिकरण को टीपीटी का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

2.3. चूंकि यह संशोधन 1 अप्रैल, 2003 से शुरू किए गए पैकेज समुद्री प्रभारों से जुड़ा है, इसलिए इस योजना की प्रासंगिक शर्त को भी उसी विशेष तारीख से लागू किए जाने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में, यह प्राधिकरण संशोधित सशर्तता को पूर्वव्यापी प्रभाव अर्थात् 1 अप्रैल, 2003 से लागू करने के टीपीटी के अनुरोध को स्वीकार करता है।

3.1. परिणामस्वरूप, उपर्युक्त कारणों से और विचार-विमर्श के आधार पर, इस प्राधिकरण के दिनांक 17 मार्च, 2003 के आदेश के पैरा 6 (iv) में निर्धारित सशर्तता को, टीपीटी के प्रस्ताव के अनुसार पुनः शब्द रूप दिया जाता है।

3.2. यह संशोधन पूर्वव्यापी प्रभाव अर्थात् 1 अप्रैल, 2003 से प्रभावी होगा।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2003-असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 4th November, 2003

No. TAMP/87/2002-TPT.—In exercise of the powers conferred under Section 49 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal of the Tuticorin Port Trust for an amendment in one of the conditionalities approved earlier vide Order No. TAMP/87/2002-TPT dated 17 March, 2003 about levy of package marine charges on main line container vessels as in the Order appended hereto.

SCHEDULE

Case No. TAMP/87/2002-TPT

The Tuticorin Port Trust

Applicant

ORDER

(Passed on this 22nd day of October 2003)

This Authority had passed an Order in case No. TAMP/87/2002-TPT on 17 March 2003 approving the proposal from Tuticorin Port Trust (TPT) for levy of package marine charges on mainline container vessels. The said Order was notified in the Gazette of India on 19 April 2003 vide Gazette Number 59.

1.2. With reference to the eligibility for the package marine charge, this Authority in its Order, inter-alia, approved the following conditionality in para 6(iv) as proposed by the port:

"(iv). The scheme will be applicable to individual lines or consortium subject to the condition that consortium shall be a registered body having a standing of atleast 5 years and the consortium should specify the number of calls to be performed by its members individually."

2.1. The TPT vide its letter dated 6 October 2003 has stated that the said condition prescribing five years standing in case of individual lines or consortium to avail the benefit envisaged in the package marine scheme is found to be very stringent. It has pointed out that there is a general consensus to dispense with this stipulation with retrospective effect from 1 April 2003 and to reword this clause as follows:

"(iv). The scheme will be applicable to individual lines or consortium subject to the condition that consortium shall be a registered body and should specify the number of calls to be performed by its members individually."

2.2. The proposed amendment will go to benefit the users. Since the proposed amendment is reportedly based on a consensus, this Authority has no reservation in accepting the TPT proposal.

2.3. Since this amendment is linked to the package marine charges introduced with effect from 1 April 2003, the relevant condition to this scheme also need to be applied from that particular date. That being so, this Authority accepts the request of the TPT to apply the amended condition with retrospective effect from 1 April 2003.

3.1. In the result, and for the reasons given above, and based on application of mind, the conditionality prescribed in para 6(iv) of the Authority's Order dated 17 March 2003 is reworded as proposed by the TPT in para 2.1 above.

3.2. This amendment will come into effect retrospectively from 1 April 2003.

A. L. BONGIRWAR, Chairman
[ADVT III/IV/143/2003-Exty.]